

3343

संख्या: संवि0क0गि0-5- / 11-2007-560(85)/2001

प्रिय,

की0 धर्मनाथि,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

साथ में,

महानिरीक्षक निबन्धान,  
उ0 प्र0, इलाहाबाद।

संस्थान विलय कर एवं निवृत्त अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक

20

सितम्बर, 2007

विषय:- उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति, 2007 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम-2005 (संख्या:28/2005) जिसे दिनांक 10-11-2006 से प्रभावी कर दिया गया है, के परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-3 के अन्तर्गत परन्तुक में बरतन(2) के बाद निम्नलिखित बरतन(3) सम्मिलित कर दिया गया है :-

(3) any instrument executed, or, on behalf of, or in favour of the developer or unit or in connection with the carrying out of purposes of the Special Economic Zone.

Explanation- For the purposes of this clause, the expressions "Developer," "Special Economic Zone" and "Unit" shall have meanings respectively assigned to them in clause (g), (z) and (zc) of section 2 of the Special Economic Zones, Act, 2005.

2- "सन्दर्भित शब्द विकासकर्ता {Developer}, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र {Special Economic Zone} एवं इकाई {Unit} के वही अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 में परिभाषित संशोधित अधिनियम में शब्दों की परिभाषा विनियत की गयी है-

**विकासकर्ता (Developer)**

"Developer" means a person who, or a State Government which, has been granted by the Central Government a letter of approval under sub-section (10) of section 3 and includes an Authority and a Co-Developer.

**विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (Special Economic Zone)**

"Special Economic Zone" means each Special Economic Zone notified under the proviso to sub-section (4) of section 3 and sub-

